



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

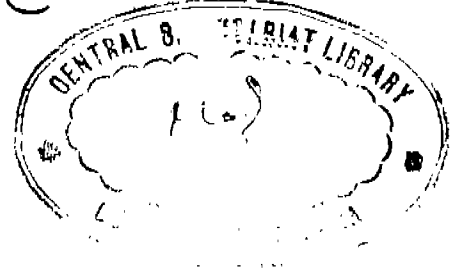
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 50]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 22, 2001/फाल्गुन 3, 1922

No. 50]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2001/PHALGUNA 3, 1922

याणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(याणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2001

प्रारंभिक निष्कर्ष

विषय : यू ए ई तथा ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित व्हाइट सीमेंट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच—प्रारम्भिक निष्कर्ष

सं. 64/1/2000-डी जी ए डी.— भारत सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 में यथा संशोधित) तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1996 को ध्यान में रखते हुए;

क. कार्य-पद्धति

1. निम्नलिखित कार्य-पद्धति अपनाई गई है:-
 - (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को नियमावली के अधीन घरेलू उद्योग की ओर से मै0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि0 तथा मै0 जे के सिंथेटिक्स लि0 से लिखित याचिका प्राप्त हुई है जिसमें यू ए ई तथा ईरान (जिसे इसके बाद सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए व्हाइट सीमेंट (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है;
 - (ii) प्राधिकारी ने उक्त नियम के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पाटन संबंधी निवेदन के प्राप्त होने की सूचना भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को दी;
 - (iii) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 2523.21 के अंतर्गत वर्गीकृत यू ए ई तथा ईरान के मूल के या वहां से निर्यातित व्हाइट

(1)

सीमेंट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरम्भ करते हुए तारीख 6 दिसम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की;

- (iv) प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, उद्योग परिसंघों तथा शिकायतकर्ता को उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया:
- (v) प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को भेजी;
- (vi) प्राधिकारी ने संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:-
 1. मै0 सवेह व्हाइट डीमेंट सी (एस डब्ल्यू सी सी), तेहरान, ईरान
 2. मै0 रास अल खैमाह कं0, यू ए ई
- (vii) नई दिल्ली स्थित यू ए ई तथा ईरान के दूतावास को भी जांच आरंभ होने की सूचना दे दी गई थी और उनसे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली भर कर भेजने का आग्रह करने का अनुरोध किया गया था ।
- (viii) व्हाइट सीमेंट के निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं/आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई:-
 1. मै0 राजहंस, राजकोट
 2. मै0 नीरव सेल्स, मोरवी
 3. मै0 सफा स्टैवलेशमेंट प्रा0 लि0, कोच्ची
 4. मै0 सहजानंद कारपोरेशन, मोरवी
 5. हिमथभाई, राजकोट
 6. प्रवीणभाई, राजकोट
 7. हसुभाई, राजकोट
 8. गिरीशभाई, मोरवी
 9. महेशभाई, राजकोट
 10. भापाभाई, राजकोट
 11. बी एम पटेल, राजकोट
 12. प्रभुदास भाई, मोरवी
 13. हरीश भाई, राजकोट
 14. जगदीशभाई, राजकोट
 15. शिवलालभाई, राजकोट
 16. विपिनभाई, वलसद
 17. दिनेश चड्ढा, सिलवासा

18. मै० लवण्य पेंट्स, अल्लापूजा
19. राजेशभाई, वलसद
20. मै० जय पेंट्स, एर्नाकुलम
21. मै० शैलकैम, कोट्टायम
22. मै० कोचीन पेंट्स, कोचीन
23. मै० उमिया मोजायक टाईल्स, वलसद
24. दयाभाई, वलसद
25. मै० क्लासिक पेंट्स, एर्नाकुलम
26. प्रवीण सी पटेल, गांधीनगर
27. गुम्मोहब्बत शेख, अहमदाबाद
28. हेमंतभाई, राजकोट
29. मै० वेस्टर्न पेंट्स, एर्नाकुलम
30. मै० कृष्णा इंडस्ट्रीज, अल्लापूजा
31. मै० मंगलम पेंट्स, कोचीन
32. फारूकभाई/सतार भाई, अहमदाबाद
33. मै० टी सी एल लि०, कोट्टायम
34. मै० हीरो कोटिंग्स, कोट्टायम
35. भरतभाई, वलसद
36. भरतभाई, राजकोट
37. ए आर शाह, अहमदाबाद
38. हसमुख पटेल, दादरा
39. कांतिभाई, गोंडल
40. मै० सुपर पेंट्स, एर्नाकुलम
41. मै० मालाबार पेंट्स, एर्नाकुलम
42. मै० कंटीनेंटल कोटिंग्स, एर्नाकुलम
43. मै० फाइव स्टार इंडस्ट्रीज, एर्नाकुलम
44. मै० प्रीमियर पेंट्स, त्रिवेन्द्रम
45. मै० च्वाईस पेंट्स, एर्नाकुलम
46. बच्चूभाई, राजकोट

(ix) उपयोगकर्ताओं/आयातकों में से मै० राजहंस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०, मै० अक्षयलक्ष्मी ट्रेडिंग प्रा० लि० तथा मै० श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स, चेन्नई द्वारा प्रश्नावली का जवाब दिया गया था । निर्यातकों में से मै० रास अल खैमाह कं०, यू ए ई, जो व्हाइट सीमेंट एवं विनिर्माण सामग्री के लिए है, ने प्रश्नावली का जवाब दिया है ।

(x) याचिकाकर्ताओं से क्षति के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जिसे प्रस्तुत कर दिया गया है ।

- (xi) प्राधिकारी ने उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के स्प में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ।
- (xii) *** यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत वैसे ही मानी गई सूचना का द्योतक है ।
- (xiii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से सूचना मांगी और उसके द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच की । इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता के राजस्थान में जोधपुर और खड़िया स्थित परिसरों की जांच की ।
- (xiv) प्राधिकारी ने लागत जांच भी की और उत्पादन की इष्टतम लागत का हिसाब लगाया और सामान्य तथा स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं का निर्माण तथा उसको बेचने की लागत का पता लगाया ।
- (xv) यह जांच 1 जनवरी, 1999 से 30 जून, 2000 तक की अवधि के लिए की गई थी ।
- (xvi) प्रारंभिक सूचना की प्रतियां व्यापक प्रचालन के लिए फिक्की, सी आई आई, एसोचैम आदि को भी भेज दी गई थी ।

ख. याचिकाकर्ता के विचार

3. याचिकाकर्ता ने अपने अनुरोधों में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए हैं-
- i) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित किया जा रहा सीमेंट संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे सफेद सीमेंट का समान उत्पाद है ।

- ii) ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं अतः याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से संपर्क किया है।
- iv) जहां तक सामान्य मूल्य का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया। तथापि, वे यू ए ई और ईरान के विनिर्माताओं द्वारा ली गई स्थानीय कीमतों के अलावा अन्य देशों को उनके निर्यातों के उचित तथा प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। अतः उन्होंने उद्योग संबंध मानदंडों के आधार पर मूल कच्चे माल तथा उपयोगिताओं की कीमतों के लिए उत्पादन की लागत के ब्यौरों के आधार पर यू ए ई और ईरान में सामान्य मूल्य का परिकलन किया।
- v) निर्यात कीमत का दावा वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए कीमत का समायोजन उतराई प्रभार, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन हैंडलिंग आदि के कारण किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत तथा दावा किए गए समायोजन के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
- vi) संबद्ध वस्तुओं के आयातों में विशेष रूप से जनवरी, 1999 से पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसमें प्रत्येक तिमाही में लगभग 8% की दर से वृद्धि हुई है।
- vii) पाटित आयातों में वृद्धि विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु विशेष रूप से समुद्री पत्तनों की निकटता तथा इन राज्यों में कुछ प्रमुख उपभोक्ताओं के कारण हुई है।
- viii) इस अवस्था में पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्रियां प्रभावित हुई हैं और इससे उनकी कीमतों में भी कमी आई है। भारतीय विनिर्माताओं को अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों में अपनी बिक्री कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। कीमतों में काफी कमी करने से क्षति हुई है और भारतीय उत्पादकों को और क्षति का खतरा हो गया जिसके अन्य क्षेत्रों में भी होने की संभावना है।

- ix) पटित आयात घरेलू उद्योग को गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि पिछले दो वर्षों में संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि दर अधिक रही है और यदि पाटनरोधी शुल्क शीघ्र ही नहीं लागू जाते हैं तो इन आयातों के पर्याप्त रूप से बढ़ने की तीव्र संभावना है ।
- x) क्षति का खतरा कीमतों में कटौती करने के रूप में भी प्रदर्शित हो रहा है जो आयातित उत्पाद की बिक्री कीमत का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होने का परिणाम है ।
- xi) संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास पर्याप्त बेशी क्षमताएं हैं । इन देशों के सफेद सीमेंट की मांग विनिर्माताओं द्वारा सृजित क्षमताओं से काफी कम है और उन्हें अपनी अधिक क्षमताओं को समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अपनी बिक्रियों में वृद्धि करने के लिए विदेशों के गतव्य स्थानों का पता लगाना पड़ता है ।
- xii) संबद्ध देशों में विनिर्माताओं के पास अपने घरेलू बाजार में वृद्धि किए बिना नई क्षमताओं का सृजन करने की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता है। जब इन देशों से निर्यातित इन स्टीकों को कलीयर करने के लिए संबद्ध वस्तुओं का पाटन करेंगे तब ये सामान निकट भाविष्य में घरेलू उद्योग के पर्याप्त क्षति पहुंचाएंगे ।

ग. आयातक और निर्यातक के विचार

4. आयातकों तथा निर्यातकों ने अपनी याचिका के समर्थन में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं :

- i) हम निवेदन करते हैं कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और मै. जे.के. सिंथेटिकस लि. द्वारा की गई शिकायत कानूनी रूप में और तथ्यात्मक रूप से अमान्य है और यह है कि यह वास्तविकता से परे है। शिकायत व्यापार दुश्मनी की उपज है। यह वास्तविक शिकायतों के आधार पर नहीं है;
- ii) हमारा यह भी विवाद है कि हमारे द्वारा आयातित सीमेंट शिकायतकर्ताओं द्वारा उत्पादित सामान के समान वस्तु है। आयातित सीमेंट और शिकायतकर्ताओं द्वारा उत्पादित सफेद सीमेंट के बीच गुणवत्ता में काफी अंतर है।
- iii) हम यह स्वीकार नहीं करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है और यह कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है;
- (iv) आयातित प्रति 50 किग्रा. सीमेंट^{के} बैग की कीमत शिकायतकर्ताओं द्वारा उत्पादित घरेलू सीमेंट कम से कम 5 रुपए से 10 रुपए प्रति किग्रा. अधिक है। जबकि आयातित उत्पाद के मामले में पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, जो कि घरेलू बाजार में प्राप्त मूल्य से अधिक रहा है। पाटनरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई का आरम्भ करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा कोई मामला बिल्कुल नहीं बनता है;

(v) शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए इस आरोप के संबंध में कि क्षति, खासकर तटवर्ती क्षेत्रों में क्षति इन क्षेत्रों में पाटित आयातों की उतराई के फलस्वरूप कीमतों में कटौती के कारण हो रही है, ऐसे किसी आरोप का कोई आधार नहीं है। तटवर्ती क्षेत्रों में कीमतों में भारी कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कोई कमी नहीं आई है। ऊपर दिये गए विवरण में कीमत कटौती के आरोप को मिथ्या सिद्ध कर दिया है;

(vi) हम मानते हैं कि विदेशी सफेद सीमेंट के आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। यहाँ तक कि वास्तविक क्षति के आरोप को उचित ठहराने के लिए युक्तिसंगत स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया;

(vii) पाटनरोधी जाँच ढ़ी शुरुआत की शिकायतकर्ता के एक तरफ़ा बयान पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इस कार्य की ओर से हमारा ध्यान हटाने के उद्देश्य से मिथ्यात्मक तथ्य और आंकड़े दिए हैं ;

(viii) याचिकाकर्ता ने बाजार में एकाधिकारी की स्थिति का लाभ तब तक उठाया है, जब तक कि हमारा उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धा के साथ उपलब्ध नहीं था। बाजार में हमारी उपस्थिति से अंतिम उपभोक्ता को लाभ मिला है, जिसको सफेद सीमेंट धन के लिए गुणवत्ता एवं मूल्य पर समझौता किए बिना उपलब्ध कराया गया है।

(ix) हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे माननीय सीमेंट (2000(122) ईएलटी 412 (न्यायधिकरण) के आदेश सं. 37-40/2000 एडी का संदर्भ लें, जिसमें माननीय सीमेंट ने सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की गणना के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच और निष्कर्ष

5. निर्यातकों, आयातकों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों जांच की गई और इन निष्कर्षों पर पहुंचते समय उन पर विचार किया गया और जहाँ उपयुक्त है, उन पर उचित स्थानों पर कार्रवाई की गई है।

6. प्राधिकारी निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किसी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया न प्राप्त होने की पुष्टि करते हैं और उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्य के आधार पर इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं।

7. उपरोक्त नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा नए निर्यातकों पर अथवा उन निर्यातकों के मामलों पर विचार किया जाएगा जो कीमतों में कटौती के इच्छुक बताए गए हैं।

ड. विद्याराशीन उत्पाद और समान वस्तु

8. शामिल उत्पाद 'सफेद पोर्टलैंड सीमेंट' है, जिसे आमतौर पर 'सफेद सीमेंट' कहा जाता है। यह एक निर्माण सामग्री है और इसका इस्तेमाल टाइलों की फ्लोरिंग, सीमेंट आधारित बाह्य सज्जा, पेंट और सीमेंट वार्निश इत्यादि जैसे गैर-संरचनात्मक प्रयोजनों में किया जाता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 25 के उपशीर्ष 2523.21 के अंतर्गत आता है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं भारत को यूएई और ईरान से निर्यात की जा रही वस्तु के समान वस्तुएं हैं। यद्यपि यूएई के निर्यातकों और आयातकों ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित और बेचा जा रहा सफेद सीमेंट श्रेष्ठ क्वालिटी का है लेकिन यहाँ यह विवाद नहीं है कि यह घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद का स्थान नहीं ले रहा है। इसलिए, जांच के प्रयोजन के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं को नियमों के अर्थों के भीतर सम्बद्ध क्षेत्र से आयाति त सफेद सीमेंट के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग

10. भारत सम्बद्ध वस्तु के तीन उत्पादक हैं, नामतः मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., मै. जे. के. सिंथेटिक्स लि. और मै0 टीसीएल लि., केरल। यह याचिका मै0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और मै0 जेके सिंथेटिक्स लि. द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर की गई है। इन दो उत्पादकों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का 90 प्रतिशत से अधिक का बनता है और इस प्रकार ये याचिका दायर करने की स्थिति में हैं। किसी भी प्रतिवादी ने इस दावे को चुनौती नहीं दी है। इसलिए, जहाँ तक याचिका दायर करने की याचिकाकर्ता की स्थिति का मुद्दा है, इस पर कोई विवाद नहीं है और प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

छ. पाटन और सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में किए गए दावों की जांच

11. धारा 9(क) (1) (ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या
- (ii) जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र

के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो:-

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत:

सामान्य मूल्य

12. प्राधिकारी ने धारा 9(क) (I) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी

तथापि, ईरान के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया था और उन्होंने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि ईरान के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है जैसाकि नियमों में प्रावधान है। घरेलू उद्योग ने परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर ईरान में सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना प्रस्तुत किया है। ईरान के निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी ने ईरान में सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन के परिकलित लागत के आधार पर किया है।

13. मै. रास अल खैमाह कं., यू ए ई जो सफेद सीमेंट और विनिर्माण सामग्री की कंपनी है ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत अपने उत्तर में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। तथापि, उसने उत्पादन लागत, घरेलू बिक्री और भारत तथा भारत से इतर देशों को किए गए निर्यातों से लाभ, घरेलू बिक्री के लिए व भारत तथा भारत से इतर देशों को निर्यात के लिए बिक्री कीमत के स्वरूप के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना नहीं प्रस्तुत की है। साथ ही प्रस्तुत किए गए गोपनीय सूचना के अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जैसाकि उपर उल्लेख किया गया है, सूचना के उपलब्ध न होने के कारण यह निर्धारित करना कठिन है कि क्या घरेलू बिक्रियाँ व्यापार के सामान्य कारोबार के रूप में की गई हैं और यह भी कि किस प्रकार के समायोजन जैसे कि कमीशन, घरेलू ~~लागू, बीमा~~, रखरखाव शुल्क इत्यादि स्वीकार्य हैं। तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजन से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का आकलन निर्यातकों द्वारा की गई घरेलू बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर करने का निर्णय

लिया है तथापि प्राधिकारी द्वारा निर्यातक को अलग से सूचित समय ढाचे में अगोपनीय अंश के साथ संपूर्ण सूचना नहीं प्रस्तुत की जाती है तो उनके पास प्रस्तुत सूचना की अनदेखी करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

निर्यात कीमत

14. मै. रास अल खैमाह कं., यूएई ने जांच अवधि के दौरान भारत और अन्यत्र किए गए अपने निर्यातों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है । भारत को किए गए निर्यात का एफ ओ बी मूल्य *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन निकलता है । ईरान के मामले में निर्यात की मात्रा और मूल्य के संबंध में डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों का उपयोग किया गया है । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर समायोजन करने के बाद जांच अवधि के लिए निवल निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन निकाला गया है ।

पाटन मार्जिन

15. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमों में यथा उल्लिखित सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांत नियमावली के अनुबंध-1 में विस्तार से दिए गए हैं । सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने गणना और तुलना व्यापार के इसी स्तर पर किया है ।

16. ईरान के लिए सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन निकाला गया है जो परिकलित उत्पादन लागत पर आधारित है । निवल निर्यात कीमत इसी प्रकार के मापदंडों के आधार पर निकाली गई है और इसके निकाले गए *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन के समान समायोजनों की अनुमति दी गई है । ईरान से संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन निर्यात कीमत का 115% बैठता है ।

17. मै. रास अल खैमाह कं. यू ए ई के मामले में उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के अनुसार जांच अवधि के दौरान औसतन (*** अमरीकी डालर प्रति मी.टन के बराबर) *** यू ए ई दिरहम प्रति मी.टन की दर से घरेलू बिक्रियां की गई हैं जिसे सामान्य मूल्य के रूप में लिया जा रहा है । जैसाकि उपर उल्लेख किया गया है भारत के लिए एफ ओ बी निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन निकाला गया है । घरेलू बिक्री कीमत और भारत के लिए एफ ओ बी निर्यात कीमत दोनों के लिए किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया है और इनकी तुलना व्यापार के समान स्तर पर की गई है । मै. रास अल खैमाह कं., यू ए ई के लिए पाटन मार्जिन निर्यातद्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर एफ ओ बी निर्यात कीमत का 43% बैठता है और प्राधिकारी इस मार्जिन का उपयोग यू ए ई के सभी निर्यातकों के लिए करने के पक्ष में हैं क्योंकि उपलब्ध सूचना के अनुसार यू ए ई में सफेद सीमेंट का केवल एक विनिर्माता है ।

ज. क्षति

पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

क्षति का निर्धारण

- (1) निर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा कि भारत में होने वाले ऐसे आयातों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में बाधा आती है;
 - (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे और घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा और पाटित आयातों की मात्रा, और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसे वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करेंगे ।
18. उपरोक्त नियम 11 के तहत अनुबंध II(iii) में यह प्रावधान भी है कि जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयातों की एक साथ ही पाटनरोधी जांच की जानी हो वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस प्रकार के आयातों के प्रभाव का एक साथ आकलन तभी करेगा जब यह निश्चित हो जाए कि प्रत्येक देश से हुए आयात से संबंधित डम्पिंग मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान

उत्पाद के आयात का तीन प्रतिशत है अथवा जहां अलग-अलग देश का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां समेकित आयात समान उत्पाद के आयात का सात प्रतिशत से ज्यादा बनता है और आयातित उत्पाद एवं समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की परिस्थिति के आलोक में आयातों के प्रभाव का एक साथ आकलन करना उपयुक्त हो ।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और पाटन का मार्जिन उपर निर्धारित सीमा से अधिक हैं । आयातों के प्रभावों का एक साथ मूल्यांकन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात कीमत भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई कीमतों के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धा कर रहे थे ।
20. उपरोक्त नियम 11, अनुबंध II के अनुसार जब हानि का पता लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान का निर्धारण करते समय डम्प्ड आयातों की मात्रा, समान उत्पाद की घरेलू बाजार कीमतों पर इनके प्रभाव और उसके फलस्वरूप ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जाता है ।

उपरोक्त के अलावा, क्षति के खतरे के संबंध में उपरोक्त नियमों के अनुच्छेद ॥ के पैरा (vii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

“(vii) वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि केवल आरोपों, अटकलबाजियों या परोक्ष संभावना पर। परिस्थितियों में बदलाव, जो ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें पाटन से क्षति होती हो, स्पष्ट तौर पर पहले से ही जान लेना चाहिए और यह अटल होता है। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्न कारकों पर विचार करेगा;

- (क) भारत में पाटित आयातों की एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर जो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाता है;
- (ख) निर्यातक की क्षमता का पर्याप्त रूप से मुक्त निपटान या अटल रूप से हुई पर्याप्त वृद्धि कोई अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार के पर्याप्त रूप से बढ़े हुए निर्यातों की संभावना को प्रदर्शित करती है।
- (ग) क्या आयात उन कीमतों पर किए गए हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण दबाव या नियंत्रित प्रभाव पड़ेगा और इससे आगे के आयातों की मांग में वृद्धि की संभावना होगी; और
- (घ) वस्तुओं के स्टॉक की जांच की जा रही है।”

21. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट रही है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक स्थिर रखना है अथवा मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक हो गया होता। भारत में घरेलू उद्योग पर पड़े प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उत्पादन, बिक्री, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली इत्यादि जैसे संकेतकों पर विचार किया जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं।

22. उपरोक्त उल्लिखित घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक मानदण्ड जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोगिता, बिक्री मात्रा इत्यादि की जांच की गई है। तथापि, पाटित आयातों पर अधिकांश स्पष्ट प्रभाव कीमतों पर पड़ा है और विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में। घरेलू उद्योग के तटीय क्षेत्रों में बिक्री में अत्यधिक गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने आगे यह उल्लेख किया है कि उन्हें अत्यधिक कीमतों में अंतर होने की वजह से उपभोक्ताओं को घरेलू उत्पाद की खरीद जारी रखने के लिए उनको मनाने में कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद उत्पादन और क्षमता उपयोगिता पर तुरंत प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता क्योंकि घरेलू बाजार का विस्तार होने के कारण, पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है।

23. आयात की महत्वपूर्ण वृद्धि दर

वर्षों से संबद्ध देशों से व्हाइट सीमेंट के आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो वर्ष 1996-97 में लगभग 1700 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 1999-2000 के दौरान 9400 मीट्रिक टन हो गई। उक्त वृद्धि दर जांच अवधि के दौरान बढ़ गई है। आयात की त्रैमासिक वार मात्रा में हुई वृद्धि निम्नानुसार है:-

आयात वृद्धि का रुख	त्रैमासिक आनुपातिक आयात मात्रा	1996-97 की तुलना में वृद्धि दर
1996-97	430	—
1997-98	986	2.29
1998-99	1295	3.01
अप्रैल-सितम्बर, 99	1475	3.43
अक्तूबर-दिसम्बर, 99	2376	5.52
जनवरी-मार्च, 00	4099	9.53
अप्रैल-जून, 00	3156	7.34
जुलाई-सितम्बर, 00	3869	8.99

आयातकों और निर्यातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यू ए ई से आयातों की मात्रा भारत में घरेलू उत्पादन का केवल लगभग 2% है और इसलिए यह क्षति का कारण नहीं है। यहां घरेलू उद्योग द्वारा यह भी बताया गया है कि फिलहाल आयात गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में केन्द्रित है। यदि इन क्षेत्रों में की गई बिक्रियों को ध्यान में रखा जाए, तो आयातों को एक बहुत महत्वपूर्ण अनुपात के रूप में निकाला जाएगा जो घरेलू उद्योग की बिक्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए काफी होगा।

24. पर्याप्त रूप से कीमतों में कमी

आयातों की पहुँच कीमत उन तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जहां घरेलू उद्योग के लिए परिवहन लागत अत्यधिक है। विशिष्ट बाजारों जैसे, सालैम, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, कोचीन, राजकोट, भावनगर, मोरवी इत्यादि में यू ए ई और ईरान से हुए आयातों से कीमतों में अत्यधिक कमी आई है जो घरेलू उद्योग की पहुँच कीमत से 14 % से लेकर 40 % तक रहती है।

25. बेशी निपटान क्षमता

आयातकों और निर्यातकों द्वारा किए गए निवेदनों के अनुसार 1999-2000 में यू ए ई में लगभग ***** मीट्रिक टन की अप्रयुक्त क्षमता थी । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार इरान में 1.6 मिलियन टन की कुल क्षमता उपलब्ध है और 1,65,000 मी.टन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जा रहा है जो 2003 के शुरु में प्रचालन में आएगी । आगे यह बताया गया है कि उपयुक्त क्षमता उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु घरेलू मांग पर्याप्त नहीं है और इसलिए विनिर्माता विदेशी बाजारों की तलाश कर रहे हैं । चूँकि इरान के निर्यातकों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है घरेलू उद्योग का यह दावा कि उनके पास उच्च अतिरिक्त क्षमताएं हैं, का सत्यापन नहीं किया जा सकता ।

26. स्टॉक

घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि मांग में अधिक वृद्धि न होने के बावजूद दुगुनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ईरान और यू ए ई के उत्पादकों ने पर्याप्त बेशी स्टॉक रखा हुआ है। ईरान के मामले में निर्यातकों से असहयोग की अनुपस्थिति में इस आरोप को सत्यापित नहीं किया जा सकता । तथ्यपि, यू ए ई से निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1 जनवरी, 1999 से 31 जून, 2000 के बीच की जांच अवधि के दौरान *** मी.टन से *** मी.टन की वृद्धि हुई है, जो पर्याप्त नहीं है ।

27. यू ए ई के आयातकों और निर्यातकों के ये तर्क कि कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात की एक बहुत छोटी मात्रा से घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ने और न ही कोई क्षति होने की संभावना है ।

तथापि यह देखा गया है कि कम कीमतों पर हुए आयात की थोड़ी सी मात्रा भी घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए बाध्य करती है क्योंकि क्रेता बेंचमार्क कीमत की मांग करना शुरू कर देते हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा उनको पेशकश की जाने वाले आयात के पहुँच मूल्य द्वारा निर्धारित होती है।

उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्यों के साथ यह तथ्य पाटित आयातों से घरेलू उद्योग के दावे को उचित सिद्ध करता है जिसके कारण उनको गंभीर क्षति होने का खतरा रहता है। उनका यह दावा कि यदि निर्यातकों का अनुचित पाटन करने का व्यवहार जारी रहता है और यदि इसकी इस स्थिति में समय से निगरानी नहीं की जाती है तो पाटन तटवर्ती क्षेत्रों के अलावा देश के अन्य भागों में भी फैल जाएगा और इससे भारतीय व्हाइट सीमेंट उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अतः प्राधिकारी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का सामना करना पड़ रहा है।

झ. कारणात्मक संबंध

- 28 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है, प्राधिकारी ने इस तथ्य को हिसाब में लिया है कि स्थानीय बाजार में पाटित कीमतों पर पाटित आयात की वृद्धि ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें उस स्तर तक कम करने के लिए बाध्य किया है जिस स्तर पर यह क्षति रहित कीमत तथा इन क्षेत्र के लिए परिवहन लागत की वसूली करने के लिए पर्याप्त नहीं है। घरेलू उद्योग को हो रही गंभीर क्षति और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के बीच कारणात्मक संबंध स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को

हो रही गंभीर क्षति के खतरे और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन के बीच कारणात्मक संबंध है।

अ. भारतीय उद्योग के हित

- 29 सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः बहाली करना है जो कि देश के सामान्य हित में है।
- 30 प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से क्वाइट सीमेंट के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्राभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव डाल सकता है। किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग के ह्रास को रोका जाएगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से यू ए ई और ईरान से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता दो या इससे अधिक आपूर्ति के स्रोत रख सकेंगे।

निष्कर्ष

31. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :

- (i) यू ए ई और ईरान से भारत को व्हाइट सीमेंट का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;
- (ii) भारतीय उद्योग को क्षति हुई है और इसको आगे और क्षति होने का खतरा है;
- (iii) यू ए ई और ईरान से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है;

32. प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के उद्देश्य से, अंतिम रूप से निर्धारण होने तक, यू ए ई और ईरान से व्हाइट सीमेंट के सभी आयातों पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं। प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

33. तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि अन्तिम निर्धारण होने तक सीमा शुल्क के कोड 2523.21 के अंतर्गत आने वाले यू ए ई और ईरान के मूल के व्हाइट सीमेंट पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से नीचे यथा निर्धारित अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। पाटनरोधी शुल्क निम्नानुसार होगा:-

देश	पाटनरोधी शुल्क (अमरीकी डालर प्रति मी. टन)
1 यू ए ई (अल रास खैमाह कंपनी समेत सभी निर्यातक)	30
2. ईरान (सभी निर्यातक)	46

ठ. आगे की प्रक्रिया

34. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों से इन निष्कर्षों के बारे में टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और उन पर अंतिम निष्कर्ष निकालते समय विचार किया जाएगा;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता तथा अन्य संबंधित ज्ञात हितबद्ध पक्षों को अलग से संबोधित किया जा रहा है, जो पत्र के प्रेषण की तारीख से 40 दिनों के अन्दर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है;

(ग) प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक निवेदन, जिसे इसके बाद लिखित रूप में दिया जाना है, करने का अवसर प्रदान किया जाएगा;

(घ) प्राधिकारी आवश्यक सीमा तक और आगे जांच करेंगे।

(ङ.) प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों को घोषणा करने से पूर्व आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया जाएगा।

एल. बी. सप्तश्रृषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2001

Preliminary Findings

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of White Cement originating in or exported from the UAE and Iran—preliminary findings

No. 64/1/2000-DGAD.— The Government of India having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed:-
 - (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s. Grasim Industries Limited and M/s. JK Synthetics Ltd., on behalf of the

domestic industry, alleging dumping of White Cement (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from the UAE and Iran (hereinafter referred to as subject countries) ;

- (ii) The Authority notified the Embassies of subject countries in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*;
- (iii) The Authority issued a Public Notice dated 6th December, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of White Cement originating from UAE and Iran classified under heading 2523.21 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975;
- (iv) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers, industry associations and to the complainant and gave them an opportunity to make their views known in writing.
- (v) According to sub-rule (3) of Rule 6 *supra*, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassies of subject countries in India.
- (vi) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following exporters:
 - 1. M/s. Saveh White Demant C.(SWCC), Tehran, Iran.
 - 2. M/s. Ras Al Khaimah Co., UAE

(vii) The Embassies of UAE and Iran in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;

(viii) The questionnaire was sent to the following users/importers of White Cement:

1. M/s. Rajhans, Rajkot
2. M/s. Nirav Sales, Morvi
3. M/s. Safa Establishment P Ltd., Kochi
4. M/s. Sahajanand Corporation, Morvi
5. M/s. Himathbhai, Rajkot
6. M/s. Pravinbhai, Rajkot
7. M/s. Hasubhai, Rajkot
8. M/s. Girishbhai, Morbi
9. Maheshbhai, Rajkot
10. Bhapabhai, Rajkot
11. BM Patel, Rajkor
12. Prabhudas Bhai, Morbi
13. Harish Bhai, Rajkot
14. Jagdishbhai, Rajkot
15. Shivilalbhai, Rajkot
16. Bipinbhai, Valsad
17. Dinesh Chadha, Silvassa
18. M/s. Lavanya Paints, Allapuza
19. Rajeshbhai, Valsad
20. M/s. Jaya Paints, Ernakulam
21. M/s. Shellcam, Kotayyam
22. M/s. Cochin paints, Cochin
23. M/s. Umiya Mosaic Tiles, Valsad
24. Dayabhai, Valsad
25. M/s. Classic Paints, Ernakulam
26. Pravin C Patel, Gandhinagar
27. Gummohabbat Sheikh, Ahmedabad
28. Hemant bhai, Rajkot

29. M/s. Western Paints, Ernakulam
30. M/s. Krishna Industries, Allapuzha
31. M/s. Mangalam Paints, Cochin
32. Farooqbhai/Satar bhia, Ahmedabad
33. M/s. TCL Ltd., Kottayam
34. M/s. Hero Coatings, Kottayam
35. Bharat bhai, Valsad
36. Bharat bhai, Rajkot
37. AR Shah, Ahmedabad
38. Hasmukh Patel, Dadra
39. Kantibhai, Gondal
40. M/s. Super Paints, Ernakulam
41. M/s. Malabar Paints, Ernakulam
42. M/s. Continental Coatings, Ernakulam
43. M/s. Five Star Industries, Ernakulam
44. M/s. Premier Paints, Trivandrum
45. M/s. Choice Paints, Ernakulam
46. Bachubhai, Rajkot

- (ix) Among the users/importers, response to the questionnaire was filed by M/s. Rajhans Distributors Pvt. Ltd., M/s. Akshayalakshmi Trading Pvt Ltd., and M/s. Sree Lakshmi Traders, Chennai. Among the exporters, M/s. Ras Al Khaimah Co., For White Cement & Construction Materials, UAE, have filed response to the questionnaire.
- (x) Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished;
- (xi) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

- (xii) ***** in this notification represents information furnished by the interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- (xiii) The Authority sought and verified information given by the domestic industry and to this end investigations were carried out at the premises of the petitioners' at Jodhpur and Kharia in Rajasthan;
- (xiv) The Authority also conducted cost investigation and worked out optimum cost of production and cost to make and sell subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles;
- (xv) The investigation covered the period from 1st January 1999 to 30th June 2000.
- (xvi) Copies of initiation notice was also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

B. PETITIONER'S VIEWS

- 3. The petitioners have made the following major points in their submissions:
 - (i) The petitioners' represent the domestic industry and white cement being produced by the petitioners' is a like product to the white cement being imported from subject countries.
 - (ii) Iran and UAE are dumping subject goods in India and the petitioner has, therefore, approached the Designated Authority for considering levy of anti dumping duty.

- (iv) Regarding the normal value, petitioners made efforts to get information on the domestic prices of subject goods in subject countries. However, they could not get a reasonable and authentic evidence of the local prices charged by the manufacturers in the UAE and Iran or for their exports to other countries. Therefore they constructed the normal value in UAE and Iran on the basis of the details of cost of production for basic raw material and prices of utilities etc., on the basis of the industry norms;
- (v) The export price has been claimed on the basis of the data compiled by the Director General Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta. Price adjustments have been claimed on account of landing charges, ocean freight, marine insurance, commission, port handling etc., to arrive at net export price.
- (vi) There has been significant increase in the imports specifically since January 1999 of subject goods which has increased approximately at the rate of 8 per cent per quarter;
- (vii) The increase of dumped imports is particularly in the coastal regions of Gujarat, Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu, particularly because of the close proximity of these places with the sea ports and some of the major consumers in these States;
- (viii) The dumped imports have at this stage affected the sales of the domestic industry and undercutting their prices. The Indian manufacturers have been forced to lower their selling prices in these regions as compared to other regions. The existence of significant price under-cutting has caused injury

and threatening further injury to the Indian producers which is likely to spread to other regions as well;

- (ix) The dumped imports are causing severe threat to the domestic industry as there has been a significant rate of increase in imports of subject goods in the last two years and there is a very strong likelihood of these imports increasing substantially should the anti dumping duties not be clamped quickly.
- (x) The threat of injury is also manifest in the form of price under-cutting which is the result of the selling price of imported product being significantly below the selling price of domestic industry;
- (xi) The exporters in subject countries are holding substantial surplus capacities. The demand of white cement in these countries is far lower than the capacities created by the manufacturers and they have to look for off-shore destinations to increase their sales to ensure reasonable utilisation of their excess capacities;
- (xii) The manufacturers in the subject countries are holding substantial surpluses in view of creation of new capacities without much increase in their domestic market. These inventories are going to cause substantial injury to the domestic industry in near future when the exporters from these countries dump subject goods to clear these stocks;

C. IMPORTERS AND EXPORTERS' VIEWS

4. The importers and exporters have expressed following views in support of their petition:

- (i) We submit that the complaint lodged by M/s. Grasim Industries Ltd., and M/s. JK Synthetics Ltd., is wholly untenable in law and fact and the same is bereft of bonafides. The complaint is the product of trade rivalry. It is not based on any genuine grievances;
- (ii) We also dispute that the cement imported by us are 'like article' to the goods produced by the complainants. There is a world of difference in quality between the imported cement and the white cement produced by the complainants;
- (iii) We do not admit that the normal value of the subject goods is significantly higher than the net export price and that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries;
- (iv) The price of the imported cement per 50 kgs bag is more than the domestic cement produced by the complainants at least by Rs.5 to Rs.10 per kg. While so, anti dumping duty is not attracted in the case of the imported product being higher than value obtained in domestic market. There is absolutely no case made out by the complainants for initiation of proceedings under anti dumping laws;
- (v) With regard to the allegation made by the complainants that the injury is being caused especially in the coastal areas on account of price suppressing resulting from dumped imports landing in these areas, there is absolutely no warrant for such an allegation.

- There has been no price undercutting and erosion in the profitability for the domestic industry in the coastal areas. The Statement given above belies the charge of under cutting;
- (vi) We submit that the domestic industry has not suffered any injury consequent to the import of foreign white cement. Not even plausible explanation offered justifying the allegation of material injury;
 - (vii) The very initiation of anti dumping investigation is based upon the one sided version of the complainants, who appear to have given distorted facts and figures in order to drive us from the trade;
 - (viii) The petitioners have enjoyed a monopoly situation in the market, until our product was made available with competence in the market. Our presence in the market, has been only to the advantage of the end consumer, to whom the white cement was made available in the market without compromise to quality and value for money;
 - (ix) We request the Designated Authority to refer to order Nos.37-40/2000-AD of the Hon'ble CEGAT, (2000 (122) ELT 412 (Tribunal) , wherein the Hon'ble CEGAT have given certain directions on methodology for calculation of normal value and dumping margins;

D. Examlnation and Findings by Authority

5. The submission made by the exporters, importers, domestic industry and other interested parties have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.

6. The Authority confirms, the absence of any direct response from the exporters from Iran in the form and manner prescribed and having made the findings with regard to exports from Iran on the basis of the fact available to it as per rule 6(8) *supra*.

7. The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking shall be considered, on request, by the Authority in accordance with the Rules *supra*.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

8. The product under consideration is “white portland cement” which is normally referred to as “white cement”. It is a construction material and used for non structural purposes such as flooring of tiles, cement based exteriors, paints and cement varnish etc. This falls within Chapter 25 of the Custom Tariff Act under the sub-heading 2523.21. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

9. The goods produced by the domestic industry are like articles to the goods being exported from UAE and Iran to India. Though the exporters from UAE and the importers in India have claimed that the white cement being manufactured and sold by them is of superior quality but there is no argument that it is not substituting the product being manufactured by the domestic industry. Therefore, for the purpose of investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as ‘like articles’ of white cement imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

F. DOMESTIC INDUSTRY

10. There are three producers of the subject goods in India namely, M/s. Grasim Industries Limited, M/s. JK Synthetics Limited and M/s. TCL Limited, Kerala. The petition has been filed by M/s. Grasim Industries Limited and M/s. JK Synthetics Ltd., on behalf of the domestic industry. These two producers account for more than 90 per cent of the total domestic production and thus have the standing to file the petition. None of the respondents have challenged this claim. Therefore, as far as the issue of standing of the petitioners to file the petition is concerned, there is no dispute and the Authority has determined that petitioners represent the domestic industry for the purpose of present investigation.

G. Dumping & examination of claims made on Normal Value & Export Prices

Normal Value

11. Under Section 9A(1)©, normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

12. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)©. However, none of the exporters from Iran responded to the Authority and have not furnished any information. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from Iran have cooperated with the Authority as envisaged under the Rules. The domestic industry has furnished information with regard to the normal value in Iran based on the constructed cost of production. In view of non cooperation from the exporters from Iran, the Authority has determined normal value in Iran on the basis of the constructed cost of production.

13. M/s. Ras Al Khaimah Co. for White Cement and Construction Materials, UAE, has furnished information regarding the domestic sales price and the export price in their response submitted to the Designated Authority. However, information regarding the cost of production, profit on the domestic sale and the exports to India and to countries other than India, sale price structure for domestic sales, for exports to India and for exports to

countries other than India, have not been provided in the prescribed format. No documentary evidence regarding ocean freight, invoices of domestic sales etc., have been furnished. Also non confidential summary of the confidential information submitted have not been furnished. Because of the non availability of information, as mentioned above, it is difficult to determine as to whether the domestic sales are in the ordinary course of trade and also as to what kind of adjustment such as commission, domestic freight, insurance, handling charges etc., are admissible. However, for the purpose of preliminary findings the Designated Authority has decided to work out the normal value and dumping margin on the basis of the information provided for domestic sales by the exporter. The Authority reserves the right to ignore the information furnished by the exporter in case complete information is not furnished along with the non confidential summary within 40 days of issue of these findings.

Export price

14. M/s. Ras Al Khaimah Co., UAE has furnished information regarding their exports to India and elsewhere during the period of investigation. The FoB export price to India works out to US\$ *** per MT. No information has been furnished regarding adjustment that can be claimed in export price as per the Rules. In the case of Iran, the DGCIS data regarding the volume and price of export has been used. After making the adjustments on the basis of information furnished by the domestic industry the net export price has been worked out as US\$*** per MT for the period of investigation.

Dumping margin

15. The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin as laid down in the Custom Tariff Act and the Anti Dumping Rules are elaborated in Annexure I to the Rules. For the purpose of the fair comparison between the normal value and export price, the Authority has made calculations and comparisons at the same level of trade.

16. The normal value for Iran based on the constructed cost of production works out to US\$ *** per MT. The net export price worked out on the basis of similar parameters and allowing similar adjustments works out to US\$ *** per MT. The dumping margin for exports of the subject goods from Iran comes to 15 % of the export price.

17. In the case of M/s. Ras Al Khaimah Co., UAE, the domestic sales have been made during the period of investigation @ *** UAE Dirhams per MT on the average (equal to US\$ *** per MT) as per the submissions made by them which is being taken as the normal value. The FoB export price to India, as stated above, has been worked out as US\$ *** per MT. No adjustments have been claimed both in the domestic sales price as well as the FoB export price to India making them comparable at similar level of trade. The dumping margin on the basis of the information submitted by the exporter comes to 43 % of the export price for M/s. Ras Al Khaimah Co., UAE and the Authority intends to use the same margin for all the exporters from UAE because as per the information available there is only one manufacturer of white cement in UAE.

H. Injury

18. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

“Determination of Injury:

- (1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;
- (2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.”

Cumulative Assessment of Injury

19. Annexure II (iii) under Rule 11 *supra* further provides that “in cases where imports of a product from

more than one country are being simultaneously subjected to Anti dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limits prescribed above. Cumulative assessment of the effects of imports are appropriate since the export prices from the subject countries were directly competing with the prices offered by the domestic industry in the Indian market.

Threat of Injury

20. Under Rule 11 *supra*, Annexure II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "*.....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.....*". Further to above, regarding threat of injury, para (vii) of Annexure II of Rules *supra*, reads as under:-

“(vii) A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, *inter alia*, such factors as:

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

(d) inventories of the article being investigated.”

21. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is

having a bearing on the state of industry as production, sales, stock, profitability, net sales realisation etc.

22. All the economic parameters affecting the domestic industry mentioned above, such as production, capacity utilisation, sales volume etc., have been examined. The capacity utilisation in case of M/s. JK White Cement during the period of investigation has been approximately ***% and that in case of M/s. Grasim Industries was***% during the period of investigation. However, the most clear effect of dumped imports has been on the prices specially in the coastal areas such as Gujarat, Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu which has caused injury to domestic industry. There has been a tremendous erosion of the sales in the coastal areas for the domestic industry and the domestic industry has further stated that they are finding it difficult to convince the consumers to continue to buy the domestic product because of the enormous price difference. Even though there may not be an immediate adverse effect on the production and capacity utilisation because of the expanding domestic market, the dumped imports are causing threat of further injury to the domestic industry in coastal areas which is spreading to interior areas as well.

23. Significant rate of increase of Import - Over the years the imports of white cement from the subject countries have increased significantly from approximately 1700 MTS in 1996-97 to approximately 9400 MTS during 1999-2000. This rate of increase has intensified during the period of investigation. The quarter wise volume of import has increased as follows:-

Imports-Increase trend	Quarterly proportionate import volumes	Rate of increase over 1996-97
1996-97	430	-
1997-98	986	2.29
1998-99	1295	3.01
April-Sept'99	1475	3.43
Oct-Dec'99	2376	5.52
Jan-Mar'00	4099	9.53
April-June'00	3156	7.34
July-Sept'00	3869	8.99

It has been argued by the importers in India and exporters from UAE that the volume of imports from UAE accounts for a very small per cent of the domestic production in India and therefore cannot cause injury. Here it has been stated by the domestic industry that the imports are concentrated at present in the coastal areas of Gujarat, Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu . If only the sales made in these areas are taken into account, imports will work out to be a very significant proportion sufficient enough to adversely affect the sales of the domestic industry.

24. Significant Price Under cutting - The landed price of the imports is significantly below the selling price of the domestic industry in the coastal areas where the transportation cost for the domestic industry is very high. In specific markets, such as Salem, Chennai, Trivandrum, Cochin, Rajkot, Bhavnagar, Morvi etc., there is a significant price under-cutting by imports from

UAE and Iran which varies from 14% to 40% of the landed price of the domestic industry taking into account non injurious price and transportation cost.

25. Surplus disposable Capacity - As per the submissions made by the importers and exporters, there was unutilized capacity in UAE of approximately ***** MTs in 1999-2000. As per the information submitted by the domestic industry, there is a total capacity of 1.16 million tones available in Iran and additional capacity of 1, 65,000 MT is being created which will become operational in early 2003. It is further stated that the domestic demand is not sufficient to ensure reasonable capacity utilisation in subject countries and hence the manufacturers have to look for markets abroad. As no response has been received from exporters from Iran, the claim of the domestic industry of their being large spare capacities could not be verified.

26. Inventories - The domestic industry has alleged that producers in Iran and UAE are holding substantial surplus stocks in view of doubling of capacities without much increase in demand. In the case of Iran, this allegation could not be verified in the absence of non cooperation from the exporters. However, as per the information given by the exporter from UAE there is increase in stock during the investigation period from *** MT to **** MT between 1st January 1999 to 31st June 2000 which is not very significant.

27. Volume and Price Effect – It is the argument of importers and exporter from UAE that a very small quantity of import as compared to the total domestic production is unlikely to have any effect on the domestic industry and cause injury. However, it is seen that even a very small quantity of import at low prices forces the

domestic industry to reduce the prices as the buyers start demanding the benchmark set by the landed value of import to be offered to them by the domestic industry as well causing severe price undercutting. This factor along with the factors mentioned in the paragraphs above, justify the claim of the domestic industry of dumped imports causing severe threat of injury to them. It is their contention that if the unfair dumping practice of exporters continues and if not timely checked at this stage, the injury would spread over to other parts of the country other than the coastal areas and would have a long term adverse impact on the Indian white cement industry. On the basis of the evidence available before it, the Authority therefore concludes that there is a serious threat of injury being caused to the domestic industry on account of dumped imports of subject goods from subject countries.

I. Causal Link

28. In determining whether injury to the domestic industry was caused by the dumped import, the Authority has taken into account the factor that it is the increased dumped import at dumped prices in localized markets which has forced the domestic industry to reduce its prices to the levels not sufficient to recover the non injurious price and the transportation cost to these areas. Therefore, the causal link between the dumped imports of subject goods from subject countries and threat of injury being faced by the domestic industry is clear. The Authority therefore concludes that there is a causal link between the dumping of subject goods from the subject countries and threat of injury being caused to the domestic industry during the period of investigation.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

29. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

30. The Authority recognises that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using White Cement and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from UAE and Iran in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

K. CONCLUSIONS

31. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) White Cement has been exported to India from UAE and Iran below its normal value;
- (ii) the Indian industry has suffered injury and is being threatened with further injury;

32. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of White Cement from UAE and Iran in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping for known exporter determined by the Authority are indicated in the paragraphs above.

33. Accordingly, the Authority recommends that provisional anti dumping duties as set out below be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of white cement falling under customs code 2523.21 originating from UAE and Iran pending final determination. The anti dumping shall be as follows:-

Country -	Anti dumping duty (US\$ per MT)
1. UAE (all exporters including M/s. Al Ras Khaimah Co.)	30
2. Iran (all exporters)	46

L. FURTHER PROCEDURE

34 The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty

- (b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of despatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
- (c) The authority would provide opportunity to all the interested parties for making oral submissions which have to be rendered thereafter in writing;
- (d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
- (e) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority